

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या:- 25/2004

आरसीएमएस नं. :- 2004/00054

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार/राजस्व/ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

—अपीलार्थी

बनाम

1. चेताराम पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी भादरा तहसील भादरा।
2. मंगलचन्द पुत्र भगवानाराम जाति ब्राह्मण निवासी भादरा
3. भंवरलाल पुत्र सोहनलाल जाति अग्रवाल निवासी भादरा तहसील भादरा।

— रेस्पोंडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी भादरा, दिनांक 16.07.2003, प्र. सं. 372/2003

अनवान चेताराम आदि बनाम सरकार

उपस्थिति:-

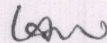
राजेश कौशिक, अभिभाषक अपीलार्थी

निर्णय

दिनांक 09.12.22

यह प्रकरण वर्ष 2003 से विचाराधीन चल रहा है। लगभग 19 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी काफी प्रयासों के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नहीं आया है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार पुराने प्रकरणों का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। इसलिए प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोंडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद पेश किया जिसमें कथन किया कि रोही मोज चक नं. 10 बीएचडी की खाता सं० 1/1 में कुल 14.801 है० कृषि भूमि है जिसमें बारानी 1.834 है०, गैरमुमकिन रास्ता 0.139 है०, नहरी 12.527 है० गै०मु० खाला 0.301 है० भूमि रिकार्ड में दर्ज है। रेस्पोंडेंट का उपरोक्त कृषि भूमि पर अपने बुजुगों के समय से राज० काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व ही कब्जा काश्त में चली आ रही है। मगर राजस्व रिकार्ड में यह भूमि सिंचाय चक काबिल काश्त दर्ज है। वादीगण ने उक्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय



राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़



ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा वाद वादी डिक्री किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. अपील में रेस्पोंडेण्ट की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया। राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।
4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरीत होने कारण पत्रावली पर मौजूद तथ्यों के विपरीत होने के कारण अपास्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। भूमी भाखड़ा क्षेत्र (कोलोनाईजेशन) में पड़ती है, इसलिए उक्त क्षेत्र में कानूनी प्रावधानों की पूर्ति के बिना खातेदारी नहीं दी जा सकती है। प्रश्नगत भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज थी जो कभी भी वादीगण के कब्जा काशत में नहीं रही है। जिसे रेस्पोंडेण्ट के नाम खातेदारी दर्ज करने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार नहीं है। रेस्पोंडेण्ट ने अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह कतई साबित नहीं किया है कि सम्वत 2012 से पहले उक्त भूमि पर उनका कब्जा काशत हो, इसके अभाव में रेस्पोंडेण्ट को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया एवं कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अपीलाण्ट को धारा 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया गया है। पत्रावली विधिक परीक्षण के हेतु जिला कलक्टर कार्यालय में चली गई थी इसलिए नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख काफी प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं हुआ है। अपील में ग्राम 10 बीएचडी की जमाबंदी संवत 2056 प्रस्तुत हुई जिसमें प्रश्नगत भूमि सिवाय चक काबिल काशत भूमि दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि सिवाय चक काबिल काशत भूमि है। परन्तु इस भूमि पर रेस्पोंडेण्टगण का कभी कब्जा काशत रहा हो ऐसा कोई साक्ष्य अपील में पेश नहीं हुआ है। चूंकि अपील में रेस्पोंडेण्ट उपस्थित नहीं हुआ है इसलिए वह अपने तथ्य इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका है, उसको सुनवाई का एक अवसर दिया जाना उचित है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत भूमि के खातेदारी अधिकार रेस्पोंडेण्ट को प्रदान किये हैं लेकिन अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व

lesio

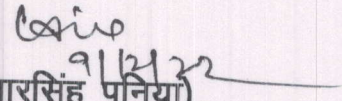
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़



अपीलाण्ट को भी सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। अपीलाण्ट के कथनों का किसी के द्वारा विरोध नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.03.2003 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुन कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।
9. निर्णय आज दिनांक 9.12.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।




 (करतारसिंह पूनिया)
 राजस्व अपील अधिकारी
 हनुमानगढ़